

राजपत्न, हिमाचल प्रदेश

(ग्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार; 17 फरवरी, 2001/28 माघ, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रावकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 2001

संख्या ई0 एक्स0 एन0-बी0(1)-1/98.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण विकय कर ग्रिधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्न, हिमाचल प्रदेश (ग्रसाधारण) में तारीख 14-12-1999 को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित, सरकार की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-बी0 (1)-1/98, तारीख 7-12-1999 द्वारा जारी, हिमाचल प्रदेश साधारण बिकय कर ग्रिधिकरण (पीठासीन ग्रिधिकारिओं के वेतन, भत्ते ग्रौर सेवा की अन्य शर्ते) निमम, 1999 में ग्रौर संशोधन करने का प्रस्ताब करते हैं।

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, इन नियमों के सम्बन्ध में कोई ग्राक्षेप करना व सुझाव देना चाहे तो वह अपने ग्राक्षेप या सुझाव इस ग्राधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की ग्रविध के भीतर, लिखित रूप में ग्राबकारी एवं कराधान ग्रायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमना-171009 को भेज

मृत्य: 1 रुपया।

मकेगा । उपर्युक्त नियत श्रवधि के भीतर प्राप्त हुए ग्राक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, पर, सरकार द्वारों इन्हें ग्रन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाए, ग्रर्थात :—

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भ --(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर ग्रिधकरण (पीठासीन ग्रिधकारियों के बेतन, भरते ग्रौर सेवा की ग्रन्य शर्ते) (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है।
 - (ii) ये निमम, राजपत्न, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 4 का संशोधन —हिभाचल प्रदेश साधारण विकय कर ग्रिधिकरण (पीठासीन ग्रिधिकारियों को वेतन, भत्ते ग्रौर सेवा की ग्रन्य शर्ते) नियम, 1999 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 4 में,—
 - (क) उप-नियम (1) में शब्दों ''भ्रायुक्त एवं सचिव'' के स्थान पर ''वित्तायुक्त एवं सचिव'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; भ्रौर
 - (क्) उप-नियम (5) में शब्दों "ग्रायुक्त एवं सिचव" के स्थान पर "वित्तायुक्त एवं सिचव के 22400--24400 रुपए" शब्द ग्रीर ग्रंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 3 नियम 5 का प्रतिस्थापन.—-उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, ग्रर्थात् :---
 - "5. पैंगन.--(1) ग्रधिकरण के लिए पीठासीन ग्रधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पैंशन का हकदार होगा:
 - परन्तु उसे ऐसी पैंशन संदेय नहीं होगी, यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम ग्रवधि की सेवा की हो ।"
 - (2) उप-नियम (1) के ग्रधीन पैंशन, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या इसके भाग के लिए, 700 रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित की जाएगी ग्रौर ग्रधिकरण में सेवा वर्षों की संख्या को विचार में लाए बिना पैंशन की श्रधिकतम रक्तम प्रतिवर्ष 3500 रुपए होगी:

परन्तु यह कि ग्रधिकरण में पदधारित करते समय प्राप्त या प्राप्ति के लिए हकदार पैंशन के संराणित भाग (यदि कोई हो) को शामिल करके किसी भी पैंशन की रकम सहित इस नियम के ग्रधीन संदेय पैंशन की संकलित रकम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित पैंशन की ग्रधिकतम रकम से ग्रधिक नहीं होगी।"

4. नियम 10 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 10 में शब्दों ''ग्रायुक्त एबं सचिव'' के स्थान पर ''वित्तायुक्त एवं सचिव'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

स्रादेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-ग्रायुक्त एवं सचिव । [Authoritative English text of this Department notification No. EXN-B (1) 1/98, dated 22-1-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd January, 2001

No. EXN-B (1)-1/98.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1999 published in Rajpatra, Himachal Pradesh, Extra-Ordinary, dated 14th December, 1999 issued vide Government Notification No. EXN-B (1) 1/98, dated 7th December, 1999 for the general information of the public.

If any person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) to make in relation to the proposed rules, he may send the same in writing to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 30 days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalising the same, namely:—

DRAFT RULES

- 1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Condition of Service of Presiding Officer) Amendment Rules, 2001.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- 2. Amendment of Rule 4.—In Rule 4 of the Himachal Pradesh Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1999 (hereinafter referred to), the said rules.—
 - (a) In sub-rule (1) for the words "Commissioner-cum-Secretary", the words "Financial Commissioner-cum-Secretary" shall be substituted; and
 - (b) In sub-rule (5) for the words "Commissioner-cum-Secretary", the words and figures "Rs, 22400—24400 of Financial Commissioner-cum-Secretary" shall be substituted.
- 3. Substitution of Rule 5.—For Rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
 - "5. Pension.—(1) Every pension appointed to the Tribunal as the Presiding Officer, shall be entitled to pension:

Provided that no such pension shall be payable if he has put in less than two years of service with he Tribunal.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum.

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule amount of any pension including commuted portion together with the of drawn while holding office in the or entitled to he drawn pension (if any), the maximum amount of pension Tribunal shall not exceed prescribed for. a judge of the High Court."

4. Amendment of Rule 10.—In Rule 10 of the said rules, for the words "Commissioner-cum-Secretary" the Words "Financial Commissioner-cum-Secretary" shall be substituted.

By order,
Sd/Commissioner-cum-Secretary.